

सं. भो.वि./सोनीपत/109-84/38696.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा.लि., कन्डली, सोनीपत, के श्रमिक श्री राम कृपाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.भो.(ई.)अम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम कृपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. भो.वि./सोनीपत/108-84/38703.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा.लि., कन्डली, सोनीपत, के श्रमिक श्री राम कवल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.भो.(ई.)अम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम कवल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. भो. वि./सोनीपत/107-84/38710.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा. लि., कन्डली, सोनीपत, के श्रमिक श्री गंगा प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.भो.(ई.)अम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री गंगा प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. भो. वि./सोनीपत/106-84/38717.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा. लि., कन्डली, सोनीपत, के श्रमिक श्री राम देव गादव तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.ओ.(ई)-अम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रयोग गठित अम न्यायालय, रोहताक, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रकरणों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है ;—

क्या श्री राम देव यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं.ओ.वी/सोनीपत/110-84/39724.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मे० सिगमा रबड़ प्रा० लि०, कुन्डली, सोनीपत, के श्रमिक श्री राम पति यादव तथा उनके प्रबंधकों के मध्य उसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;—

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए. ओ. (ई)-अम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रयोग गठित अम न्यायालय, रोहताक, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रकरणों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है ;—

क्या श्री राम पति यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ. वि/सोनीपत/65-84/39731.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मे० सिगमा रबड़ प्रा० लि०, कुन्डली, सोनीपत, के श्रमिक श्री श्री राम-III तथा उनके प्रबंधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.ओ.(ई)-अम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रयोग गठित अम न्यायालय, रोहताक, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रकरणों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है ;—

क्या श्री श्री राम-III की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं.ओ. वि/सोनीपत/66-84/38738.—चूंकि हरियाणा राज्यपाल की राय है कि मे० सिगमा रबड़ प्रा० लि०, कुन्डली, सोनीपत, के श्रमिक श्री राम निवास-I तथा उनके प्रबंधकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.ओ.(ई)-अम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रयोग गठित अम न्यायालय, रोहताक, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रकरणों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है ;—

क्या श्री राम निवास-I की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?